भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1801

उत्तर देने की तारीख 29 जुलाई, 2026 (बुधवार)

7 श्रावण, 1948 (शक)

प्रश्न

पीएम-डेवाइन योजना का कार्यान्वयन

†1801. **श्री तापिर गावः**

श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेलः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल (पीएम-डेवाइन) के अंतर्गत राज्य-वार स्वीकृत, पूर्ण तथा कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं सहित अब तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आवंटित, जारी तथा व्यय की गई धनराशि तथा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आवंटित एवं जारी की गई धनराशि का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या पीएम-डेवाइन योजना के अंतर्गत कोई नई परियोजना स्वीकृत की गई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन तथा उनकी परिणाम-आधारित निगरानी सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग) अक्तूबर 2022 में इस स्कीम की शुरुआत से लेकर दिनांक 30.06.2026 तक, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-डिवाइन) के तहत कुल 53 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है, जिनकी कुल लागत 6501.79 करोड़ रुपये है। इनमें से 344.01 करोड़ रुपये की लागत वाली 4 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। राज्य-वार जानकारी **अनुबंध** में दी गई है।

वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान इस स्कीम के तहत आवंटित धनराशियों और किए गए व्यय का विवरण इस प्रकार है:

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	**वित्त वर्ष**	**आवंटन**	**उपयोग**
1	2025-26	1454.22 (आरई)	1422.96
2	2026-27	2300 (बीई)	778.91 (दिनांक 30.06.2026 तक जारी)

(घ) मंत्रालय राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकों, जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प्ड फोटोग्राफों का उपयोग करके डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी, मंत्रालय/उत्तर पूर्वी परिषद/फील्ड तकनीकी सहायता इकाइयों (एफटीएसयू)/परियोजना गुणवत्ता प्रबोधन (पीक्यूएम)/तृतीय पक्ष तकनीकी निरीक्षण (टीपीटीआई) एजेंसियों आदि के अधिकारियों द्वारा फील्ड निरीक्षण और स्थल दौरों के माध्यम से पीएम-डिवाइन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

इन समीक्षाओं के माध्यम से, कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं, यदि कोई हों, की पहचान की जाती है और राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजना निगरानी को मजबूत करने, कार्य-निष्पादन में तेजी लाने, निधि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने और कार्यान्वयन कार्यक्रम का पालन करने की सलाह दी जाती है।

*****

अनुबंध

'पीएम-डेवाइन योजना का कार्यान्वयन' विषय पर लोक सभा में दिनांक 29.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1801 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक **30.06.2026** तक पीएम-डिवाइन के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की राज्य-वार स्थिति

क्र. सं.	**राज्य**	**स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या**	**परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत (राशि करोड़ रुपये में)**	**दिनांक 30.06.2026 तक जारी कुल धनराशि (राशि करोड़ रुपये में)**	**पूर्ण परियोजनाओं की संख्या**
1	अरुणाचल प्रदेश	6	832.80	214.31	-
2	असम	4	1402.50	745.53	-
3	मणिपुर	7	561.00	279.78	-
4	मेघालय	7	773.90	339.99	-
5	मिजोरम	2	595.24	236.29	-
6	नागालैंड	7	552.83	307.12	-
7	सिक्किम	5	561.11	437.99	3
8	त्रिपुरा	6	619.18	310.43	-
9	केंद्रीय एजेंसी	9	603.23	214.71	1
	कुल	**53**	**6501.79**	**3086.17**	**4**

*****